संपादकीय जागरण

बुधवार, 11 अप्रैल, 2018 : वैशाख कृष्ण 10 वि. 2075

शब्द संवेदनाओं के सूत्रधार होते हैं

जीएसटी की रफ्तार

वस्तु एवं सेवाकर यानी जीएसटी के तहत 15 अप्रैल से पांच और राज्यों मे राज्य के भीतर ही माल ढुलाई के लिए ई-वे बिल सिस्टम लागू करने की तैयारी यह बताती है कि कर्नाटक में इस सिस्टम के अमल का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा। इसके बावजूद सरकारी तंत्र को इसके लिए सचेत रहना होगा कि पांच राज्यों में इस व्यवस्था के अमल में किसी तरह की बाधा न खड़ी होने पाए, क्योंकि तभी वह जल्द से जल्द अन्य राज्यों में ई-वे बिल सिस्टम लागू करने में समर्थ हो सकेगी। राज्यों के भीतर ही माल ढुलाई के लिए ई-वे बिल व्यवस्था को लागू करने की तैयारी इसका भी सूचक है कि एक से दूसरे राज्यों के बीच माल ढुलाई में इस व्यवस्था को लागू करने के सकारात्मक नतीजे हासिल हुए हैं। चूंकि ई-वे बिल सिस्टम का उद्देश्य माल ढुलाई के पुराने तौर-तरीकों के जरिये की जाने टैक्स चोरी को रोकना है इसलिए कारोबार जगत के लिए भी यह आवश्यक है कि वह पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा बने। कारोबार जगत से ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा जीएसटी के अन्य नियमों के पालन के मामले में भी है, क्योंकि ऐसे प्रसंग सामने आ रहे हैं जो यह इंगित करते हैं कि जीएसटी की चोरी जारी है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कंपोजीशन स्कीम के जरिये व्यापक स्तर पर टैक्स चोरी की आशंका को देखते हुए जीएसटी काउंसिल 'रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म' जल्द से जल्द लागू करना चाह रही है। उम्मीद है कि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में इस पर कोई सहमति बन जाएगी। यदि 'रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म' अमल में आ जाता है तो यह टैक्स चोरी रोकने का एक और जतन होगा। विडंबना यह है कि ऐसे कुछ और जतन किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है और इसका कारण यही है कि कारोबार जगत का एक हिस्सा छल-छद्म से टैक्स बचाने से बाज नहीं आ रहा है।

यह सही है कि जीएसटी का तंत्र अभी भी कई जटिलताओं से लैस है, लेकिन यह ठीक नहीं कि एक ओर जटिल प्रावधानों की शिकायत की जाए और दूसरी ओर टैक्स बचाने-छिपाने का काम भी किया जाए। ऐसा होगा तो फिर जीएसटी काउंसिल भी व्यवस्था के छिद्रों को भरने के लिए नए-नए उपाय तलाशने को विवश होगी, क्योंकि राजस्व हानि की अनदेखी नहीं की जा सकती। जीएसटी काउंसिल डाल-डाल तो टैक्स बचाने वाले पात-पात, ऐसा कोई माहौल कारोबार जगत के लिए ठीक नहीं। यह किसी से छिपा नहीं कि जुलाई-दिसंबर के बीच जीएसटी नेटवर्क में फाइल रिटर्न्स की छानबीन के दौरान यह संदेह उपजा कि कारोबारियों ने करीब 34 हजार करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी छिपा ली। इसी तरह चंद दिनों पहले अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने देश भर में छापामारी करके सौ से ज्यादा प्रतिष्ठानों में चार सौ करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया। इन प्रतिष्ठानों ने जीएसटी वसूल तो लिया, लेकिन उसे सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया। निःसंदेह जीएसटी को और सुगम बनाने एवं सही तरह से टैक्स दे रहे कारोबारियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, लेकिन इसी के साथ टैक्स चोरी की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की भी जरूरत है।

जनसुनवाई

लखनऊ से बेंगलुरु जाने वाले विमान में एक डाक्टर ने एयर होस्टेस से शिकायत की कि मच्छर बहुत काट रहे हैं। एयर होस्टेस ने दिक्कत दूर करने के बजाय उल्टा अभद्र व्यवहार किया। कहा, मच्छर तो हर जगह हैं, बेहतर होगा आप यह देश छोड़कर चले जाओ। डाक्टर का सामान विमान से फेंक दिया गया और उन्हें लिए बिना फ्लाइट बेंगलुरु उड़ गई। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में यात्रियों को इस तरह की असुविधाओं का सामना तो अक्सर ही करना पड़ता है लेकिन, अब तो अच्छी सेवा का दम भरने वाला निजी क्षेत्र भी ग्राहकों के साथ अमानवीय बर्ताव करने लगा है। प्रायः ही निजी बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा भी ग्राहकों को परेशान करने की शिकायतें सुनाई देती हैं। सरकारी क्षेत्र की निंदा तो लोग मजे लेकर करते हैं लेकिन, किसी दुकान से खरीदा एक फ्रिज खराब निकल जाए तो वापस कराने या पुर्जा बदलवाने में इन्हीं लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ट्रेनों में यात्रियों से बदसलूकी की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं।

> इस विषय को यदि राज्य सरकार अपनी चिंताओं में शामिल कर ले तो बेशक अंतर पड़ेगा।

ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने यहां नागरिक अधिकारों को लेकर सजगता और चिंता नहीं है। जो परेशान होता है वह पहले तो इसे अपना भाग्य मानकर चुप रह जाता है और कहीं उसने शिकायत करने का साहस दिखाया तो सुनवाई में बहुत समय लग जाता है। उपभोक्ता फोरम में लोगों को न्याय मिलता है पर वहां भी मामले यदि जल्दी जल्दी निपटने लगें तो लोगों का भरोसा जमेगा और वहां आने के लिए वे प्रोत्साहित होंगे। इस विषय को यदि राज्य सरकार अपनी चिंताओं में शामिल कर ले तो बेशक अंतर पड़ेगा। इतने विभागों में एक विभाग जनसुनवाई का भी हो सकता है जिसके मंत्री या सचिव से आम लोग सरकारी और निजी क्षेत्र से हुई दिक्कतों का समाधान पा सकें।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या दलितों को लेकर विपक्ष की मुहिम में वोट बैंक की चिंता अधिक है?

आज का सवाल
क्या आप वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु के बयान से सहमत हैं कि भारत ट्रेड वार का फायदा उठाने की स्थिति में है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

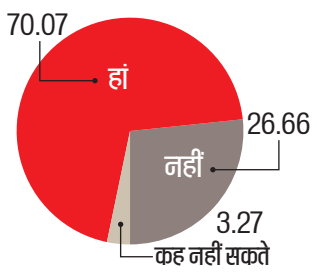

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

उन्नति का मूल नहीं अंग्रेजी भाषा

संक्रान्त सानु

कोई भी समृद्ध देश अपनी भाषाओं को छोड़ कर किसी गैर भाषा के प्रयोग से विकसित नहीं हुआ। आज भी विकसित देश अपनी भाषा के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं

नए शैक्षिक सत्र से कई राज्य स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अंग्रेजी माध्यम के पांच हजार सरकारी स्कूल चलाने का एलान किया है। तर्क है कि अभिभावक ही अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की मांग कर रहे हैं और इसी कारण वह हिंदी माध्यम स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदल रही है। इस पर यह प्रश्न उठेगा ही कि आखिर अभिभावक अंग्रेजी की क्यों मांग कर रहे हैं? और क्या ऐसी मांग को पूरा करना राज्य और देश के हित में है? आज अंग्रेजी व्यवसाय, नौकरी और विज्ञान एवं तकनीक से जुड़ गई है। इस सबके फलस्वरूप वह समाज में सम्मान का प्रतीक बन गई है। ऐसे में अंग्रेजी की ओर रुझान स्वाभाविक ही लगता है, लेकिन हम यह नहीं पहचान रहे हैं कि अंग्रेजी के महत्व का एक भ्रम जाल सा फैलाया गया है। इसकी जड़ में सरकार की गलत नीतियां हैं। भारत में अंग्रेजी का वर्चस्व वैश्विक अनिवार्यता के कारण नहीं है। विश्व के समृद्ध देश अपनी-अपनी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं और निज भाषा ही उनकी उन्नति का मूल है। मुझे विश्व के करीब 35 देशों में जाने का अवसर मिला और मैंने यह पाया कि हर एक विकसित देश अपनी भाषा के आधार पर आगे बढ़ रहा है। कोई भी विकसित देश जन भाषाओं को छोड़कर किसी गैर भाषा के प्रयोग से विकसित नहीं हुआ। हर विकसित देश तकनीक-विज्ञान और व्यवसाय में जन भाषा का प्रयोग कर रहा है। अपनी ही भाषा के आधार पर इन देशों में नौकरियां भी मिलती हैं और उच्च कोटि का शोध भी होता है। आखिर इस सबके बावजूद भारत में अंग्रेजी का बोलबाला क्यों है? अंग्रेजी-माध्यम के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की होड़ क्यों है? यह इसलिए है, क्योंकि सरकार की नीतियों ने अंग्रेजी को ऊंचे ओहदे पर कायम रखा है।

सरकार उच्च कोटि के सभी संस्थान आइआइटी, आइआइएम, एम्स इत्यादि केवल अंग्रेजी माध्यम में चलाती है। सरकार की नीति के कारण ही अधिकतर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय केवल अंग्रेजी में कार्य करता है। भारत सरकार अधिकतर परीक्षाओं में अंग्रेजी को माध्यम ही नहीं बनाती, अपितु अनिवार्य भी करती है। एसएससी जैसी परीक्षा के लिए भी अंग्रेजी अनिवार्य है। इसका परिणाम यह निकलता है कि विद्यार्थियों का सबसे अधिक परिश्रम विषय समझने की जगह अंग्रेजी से जूझने में निकल जाता है। यह भावुक बात नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक सत्य है। अनेक वैज्ञानिक शोध यह साबित कर चुके हैं कि मातृभाषा में पढ़ने से बच्चे की बुद्धि का सबसे अच्छा विकास होता है। दशकों से यूनेस्को का भी यही विमर्श है। भारत में भी हाल में आइबीसी के शोध ने साबित किया कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु माध्यम में पढ़ रहे बच्चों की विज्ञान और गणित की समझ अंग्रेजी-माध्यम में पढ़ रहे बच्चों से कहीं अच्छी थी। जापान, रूस, चीन आदि देश अपनी भाषा में उच्च शिक्षा देने के कारण ही बहुत तेजी से विज्ञान और तकनीक में प्रगति इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि वहां छात्रों को अपनी भाषा में विषय को समझने में आसानी होती है। इसके विपरीत देश में अंग्रेजी का वर्चस्व विकास का सबसे बड़ा अवरोधक बन गया है। हम देश की बुद्धि का हरण कर रहे हैं और अंग्रेजी लाद कर बच्चों को मानसिक विकलांग बना रहे हैं। इन गलत नीतियों के कारण ही अभिभावक अंग्रेजी के पीछे दौड़ रहे हैं। समस्या अभिभावकों की नहीं है, समस्या गलत व्यवस्था की है। आखिर इसका समाधान क्या है? हर स्तर पर भारतीय भाषाओं का विकल्प होना चाहिए, चाहे वह प्रबंधन की पढ़ाई हो या चिकित्सा की अथवा तकनीक की। सरकार को भाषा को व्यवसाय से जोड़ना होगा।

अवधेश राजपूत

हर राज्य सरकार एलान कर सकती है कि सभी निजी उद्योग सरकार से संवाद केवल उस प्रदेश की भाषा में करें। इससे भाषा की मांग बढ़ेगी। निजी उद्योग भारतीय भाषाओं में समान अवसर प्रदान करें, इसे भी नीतिगत रूप से लागू किया जा सकता है। कुछ समय के लिए भारतीय भाषा के माध्यम में पढ़े लोगों को सरकारी नौकरी में कुछ प्रतिशत आरक्षण भी दिया जा सकता है। यह भी आवश्यक है कि भारतीय भाषाओं को तकनीक के साथ जोड़ा जाए। आज जब कोई बच्चा स्कूल में कंप्यूटर सीखता है तो केवल अंग्रेजी में। वह भारतीय भाषाओं में टाइप करना तक नहीं जानता। अपनी भाषा में तकनीक की जानकारी से सृजन शक्ति बढ़ेगी, नए-नए आविष्कार होंगे। भाषा को केवल पुरातन संस्कृति या साहित्य ही नहीं, आधुनिकता का भी वाहक बनाना अनिवार्य है। अंग्रेजी सीखने में कोई आपत्ति नहीं है। सरकार अपने स्कूलों में भाषा के रूप में अंग्रेजी सिखाए। समस्या तब आती है जब अंग्रेजी को माध्यम बना दिया जाता है। जब बच्चे को भाषा ही नहीं आती तो वह उस भाषा में कोई अन्य विषय कैसे सीखेगा? क्या सरकार ने इस पर वैज्ञानिक रूप से कोई शोध किया है? सरकारें आठवीं कक्षा में अंग्रेजी माध्यम सरकारी स्कूलों को हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूलों से माप लें। किन स्कूलों के बच्चे गणित को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं?

मैंने अनेक वर्षों तक कई देशों में कंप्यूटर के क्षेत्र में सक्रियता से काम किया है। आज इजरायल कंप्यूटर में बहुत आगे है। वहां पर तकनीक की पढ़ाई हिब्रू भाषा में होती है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट में रूस के कंप्यूटर इंजीनियरों को नौकरी दी। उन्हें न के बराबर अंग्रेजी आती थी, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान में अंग्रेजी नहीं, बल्कि गणित और तर्क की समझ चाहिए। आज चीन चीनी भाषा में कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा देकर अमेरिका से भी आगे निकल रहा है। गणित और तर्क की इस दुनिया में अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में धकेलकर हम उन्हें पीछे ही रख रहे हैं।

यदि भारत सरकार हर राजकीय भाषा में एक-एक आइआइटी और आइआइएम खोल दे तो भारतीय भाषाओं का दर्जा और समाज में उसके प्रति रुचि तत्काल बढ़ जाएगी। कल को अगर उत्तर प्रदेश सरकार एलान कर दे कि निजी उद्योगों के टेंडर केवल हिंदी में ही मान्य होंगे तो अगले दिन ही निजी उद्योगों में हिंदी की मांग बढ़ जाएगी और इसी के साथ सभी की रुचि हिंदी के प्रति बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रांत उत्तर प्रदेश यदि एक देश होता तो आबादी के लिहाज से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश होता। इससे कहीं छोटे-छोटे देश अपनी भाषाओं में सब काम कर रहे हैं। विश्व की वास्तविकता अंग्रेजी नहीं है। विश्व के तमाम बहुराष्ट्रीय उद्योग भी अंग्रेजी पर आधारित नहीं हैं। वैश्वीकरण अंग्रेजीकरण नहीं है। हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन पंक्तियों को केवल भावुक ही मान लिया- निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। यह केवल भाव नहीं, एक वैज्ञानिक तथ्य है। यह एक भ्रम समाज में व्याप्त हो गया है कि अंग्रेजी से ही हमारी उन्नति होगी। सरकार का काम इस भ्रम को दूर करना है न कि उसमें शामिल होना, लेकिन उस राष्ट्रवादी सोच की सरकार को क्या कहें जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार अपनी जड़ें काटने पर तुली है? सरकार को अंग्रेजी की भेड़-चाल छोड़ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

(लेखक आइआइटी स्नातक, माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व अधिकारी और भारतीय भाषाओं में विज्ञान की पुस्तकों के प्रकाशक हैं)

response@jagran.com

दलित हितैषी दिखने की दौड़

राजीव सचान

दलितों के लिए चिंतित नेताओं की कमी नहीं, पर ऐसे नेता मुश्किल से ही दिखते हैं जो उनकी अपेक्षाएं समझने में समर्थ हैं

अब शायद ही कोई इससे अपरिचित हो कि खुद को दलित हितैषी दिखाने की कोशिश में कांग्रेस ने किस तरह राजघाट पर फर्जी उपवास करके अपनी फजीहत कराई। जातीय हिंसा के विरोध और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए छोले-भटूरे खाकर उपवास में बैठना या फिर इसी आयोजन में सिख विरोधी दंगों में आरोपित नेताओं का नजर आना महज एक भूल नहीं कही जा सकती। यह सब इसलिए हुआ, क्योंकि राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेसी नेता दलित हितों के नाम पर दिखावा करने तक सीमित थे। उनका एक मात्र उद्देश्य दलित हित की चिंता का ढिंढोरा पीटते हुए प्रचार पाना और केंद्र सरकार को दलित विरोधी साबित करना था। इसी बात को दूसरे शब्दों में इस तरह भी लिखा जा सकता है कि कांग्रेस दलितों को बरगलाने की कोशिश में थी। दरअसल जब कथनी और करनी में अंतर होता है तो पोल खुल ही जाती है। कांग्रेस के दुर्भाग्य से उसकी पोल राहुल गांधी के उपवास पर बैठने के पहले ही खुल गई। चूंकि उसके पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं बचा था इसलिए दलितों की उपेक्षा और अनदेखी के आरोपों से दो-चार भाजपा उस पर हमलावर हो गई, लेकिन इसमें संदेह है कि कांग्रेस को कोसने से उसका काम बनेगा। वैसे भी विपक्षी दल इस कोशिश में हैं कि भाजपा को दलित विरोधी ठहराया जाए। इस कोशिश में अन्य दलों के साथ वह समाजवादी पार्टी भी सक्रिय है जो संप्रग सरकार के समय एससी-एसटी कर्मियों की प्रोन्नति में आरक्षण संबंधी विधेयक को रोकने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाए थी और जो मायावती की ओर से बनवाए गए पार्कों में अस्पताल खोलना बेहतर समझ रही थी।

जिन मायावती ने 2007 में सत्ता में आते समय एससी-एसटी एक्ट को लेकर करीब-करीब वैसे ही दिशानिर्देश जारी किए थे जैसे हाल में सुप्रीम कोर्ट ने दिए वह इन दिनों यह साबित करने की कोशिश में हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दरअसल सरकार का फैसला है। स्पष्ट है कि दलित हित के नाम पर छल-छद्म का भी सहारा लिया जा रहा है। यह तय है कि अगले आम चुनाव तक राजनीतिक दलों के बीच यह नकली दौड़ जारी रहेगी कि दूसरों के मुकाबले सबसे बड़े दलित हितैषी वे खुद हैं। इसके लिए झूठ का सहारा लेने से भी बाज नहीं आया जाएगा, यह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान से साबित होता है कि एससी-एसटी एक्ट को तो हटा दिया गया है। सच्चाई यह है कि दलित हित के मामले में कोई भी राजनीतिक दल ईमानदार नहीं। सबकी दिलचस्पी केवल दलितों के वोट हासिल करने में ही है। यही कारण है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उत्पीड़न एवं भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। यह एक तथ्य है कि दलितों के उत्पीड़न और भेदभाव के तमाम मामलों में राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं अथवा उनके समर्थकों का ही हाथ होता है। अगर हर राजनीतिक दल दलितों का हितैषी है और उन्हें बराबरी का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है तो फिर ऐसे आंकड़े क्यों सामने आ रहे हैं कि दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं? जाहिर है कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि दलित हित के मामले में राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में अंतर है। वे कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। आखिर कितने ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनमें सक्षम दलित नेता सरकार या संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं?

भाजपा का यह दावा सही तो है कि उसके पास अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सांसदों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन क्या इस संख्याबल की झलक सरकार और संगठन के स्तर पर भी दिखती है? भाजपा की मुसीबत इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि उसके कुछ दलित सांसद यकायक नाराज हो उठे हैं। यह बात और है कि यह नाराजगी भी फर्जी ही अधिक है। एक दलित सांसद को यकायक संविधान और आरक्षण इसलिए खतरे में नजर आने लगा, क्योंकि उनके पसंदीदा ठेकेदार को सड़क निर्माण का ठेका नहीं मिला। इसी तरह एक अन्य दलित सांसद इसलिए नाराज हो गए, क्योंकि वन विभाग की जमीन को अपना बताने के उनके दावे को शासन-प्रशासन ने सही नहीं माना। निःसंदेह दलितों की दशा में सुधार न होने का एक बड़ा कारण ऐसे दलित नेता भी हैं जो अपने समाज के बजाय अपने स्वार्थ की चिंता अधिक करते हैं।

उत्तर प्रदेश में जबसे सपा-बसपा में तालमेल हुआ है तबसे इन दलों से भाजपा में आकर सांसद बने नेता फिर से इन्हीं दलों में वापसी का जतन कर रहे हैं। यह जतन इसलिए नहीं किया जा रहा कि सपा और बसपा दलित हित के प्रति समर्पित हो गए हैं। असली कारण यह है कि इन दोनों दलों के टिकट पर जीत के आसार बढ़ गए हैं। ऐसे आसार बढ़ने का एक कारण यह भी है कि पहले लोकसभा और फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा को बढ़-चढ़कर वोट देने वाले दलितों को यह लगने लगा है कि उनके वोट तो ले लिए गए, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया गया। अगर भाजपा नेतृत्व दलित समाज के इस अहसास को दूर नहीं कर सका तो इसके लिए वह अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकता। यह सही है कि विकास एक ऐसा मसला है जो जाति-संप्रदाय की विभाजन रेखाओं को कम करने का काम करता है, लेकिन जिस देश में जाति-संप्रदाय की राजनीति एक हकीकत हो वहां यह नहीं हो सकता कि वंचित वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व देने से बचा जाए।

निःसंदेह देश में दलित नेताओं अथवा उनके तथाकथित हितैषी नेताओं की कमी नहीं, लेकिन ऐसे नेता मुश्किल से ही दिखते हैं जो उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को सही तरह समझने में समर्थ हों। एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर आयोजित भारत बंद के दौरान केवल इसलिए उग्रता देखने को नहीं मिली कि अन्य दलों ने लोगों को उकसाने का काम किया अथवा हिंसा का सहारा लेने में संकोच नहीं किया। उग्रता का एक कारण यह भी रहा कि दलित समाज अपने अधिकारों के हनन को लेकर आशंकित था। इस आशंका ने उसकी बेचैनी बढ़ा दी थी, लेकिन भाजपा समेत अन्य दलों को इस बेचैनी का कहीं कोई आभास ही नहीं था। वे जमीनी हकीकत से अनजान थे। यह राजनीतिक नेतृत्व की सामूहिक विफलता के अलावा और कुछ नहीं। बेहतर हो कि देश के सभी राजनीतिक दल खुद को दलित हितैषी दिखाने की बेजा दौड़ लगाने के बजाय दलित समाज की बेचैनी के मूल कारणों को समझें।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सत्य का सौरभ

सत्य साध्य है और असत्य श्रमसाध्य। हम बड़े प्रयास से निरंतर अपने को ढकते जाते हैं और तब गढ़ते हैं असत्य की प्रतिमा। सत्य शिशु का स्वभाव है। असत्य को ग्रहण करने में उसे बड़ा श्रम करना पड़ता है। शिशु स्वभाव से निश्छल होता है, परंतु हम बड़े श्रम से उसे असत्य सिखाते रहते हैं। हमारी यह मिथ्या धारणा है कि उसे दुनियादारी सिखाने के लिए असत्य का पाठ पढ़ाना जरूरी है। ऐसा करते रहने से वह झूठ के अंधेरे में भटकने के लिए मजबूर हो जाता है। अबोध बालक शत्रु-मित्र में भेद करना नहीं जानता है। वह दोनों को देखकर मुस्करा देता है और दोनों की गोद में जाने के लिए आतुर दिखाई देता है। हम उसके मन में भेद पैदा करते हैं। बालक के कोमल मन पर हम बड़े सलीके से असत्य के विष का लेप करते रहते हैं।

बालक जाति-पांति नहीं जानता। वह तो निरंतर समभाव में रहता है। उसके भीतर नफरत की दीवार हम स्वयं खड़ी करते हैं। हम उसके सामने वर्जनाओं की बाधाएं खड़ी कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप वह सत्य के मार्ग से भटक जाता है। यही भटकन उसे हैवान बना देती है। हर व्यक्ति दावे के साथ कहता है कि उसे असत्य से नफरत है। मुझसे सत्य छिपाया नहीं जाता, परंतु होता है इसका उलटा। पति पत्नी से, मित्र मित्र से, सहयोगी अधिकारी से सत्य को छिपाता है। जब हम पग-पग पर असत्य का व्यवहार करेंगे तो सत्य का दीदार कैसे होगा? असत्य हमारे भीतर इतना गहरा पैठ गया है कि धुरंधर तत्वचिंतक भी दोहरी मान्यताएं ढोते रहते हैं। सत्य का सौरभ पाने के लिए मन की कुटिलताएं और चित्त की काई को साधना के मंजन से साफ करना होगा।

सत्य के अमूल्य रत्न को पाने के लिए हमें कुछ मूल्य तो चुकाना ही होगा। वह मूल्य चुकाया था हमारे ऋषियों ने। वे सत्य की खोज में जंगलों और पहाड़ों में अखंड साधना करते रहे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ज्ञान की खोज में भारत आया था। सत्य की तलाश में वह गुरुकुलों और आश्रमों में गया। यहां से योग्य शिष्यों को लेकर चीन वापस गया और वहां सत्य के ज्ञान का बीज बोया। ह्वेनसांग भारतीय धर्म-दर्शन की कुछ पांडुलिपियों को साथ ले गया, जिनमें साधना का सार था। इस प्रकार विश्व में पहुंचा भारत का ज्ञान-सूर्य। इन पांडुलिपियों में साधकों के जीवन का तप छपा है। इसे पुनः प्रकाशित करना होगा।

डॉ. दुर्गादत्त पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

नई तकनीक से बढ़ेगा रोजगार

रोजगार नीति मांग रही नई रणनीति शीर्षक से लिखे अपने लेख में डॉ. भरत झनझुनवाला ने रोजगार को लेकर तीन सुझाव दिए हैं। जिसमें पहला रोजगार सृजन के स्थान पर सेवा क्षेत्र पर अधिक जोर देना, दूसरा पूरे देश में फ्री वाई-फाई उपलब्ध कराना और तीसरा रोबोट तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर टैक्स लगा कर उसको हर व्यक्ति में वितरित कर देना हैं। फ्री वाई-फाई तो बहुत अच्छी बात है, परंतु बाकी की दो सुझावों का कोई उपयोग समझ नहीं आ रहा है। यदि हम उस तकनीक को बढ़ावा देने से रोक देंगे जिसमें आगे चल कर पूरे विश्व को बदलने की क्षमता है तो भारत विश्व शक्ति बनने की राह में पीछे ही रह जाएगा। ऐसे में रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक पर टैक्स लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, बल्कि सरकार को इस क्षेत्र में और सहयोग देना चाहिए, क्योंकि यही देश का भविष्य है। इस क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाएं हैं और भारत के युवाओं में इस तकनीक में पारंगत होने के गुण भी हैं।

अनुभव कुश, एबी नगर, उन्नाव

शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता

हत्याकांड, भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्षता से जांच करने के लिए सीबीआइ की भूमिका सराहनीय है। किसी भी मामले में प्राथमिक स्तर पर पुलिस जांच की विश्वसनीयता घटती जा रही है। आरुषि हत्याकांड मामले में सीबीआइ को जांच का अधिकार मिलने से पहले ज्यादातर साक्ष्य नष्ट हो चुके थे। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की हत्या के आरोप में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सीबीआइ जांच में सामने आया कि ड्राइवर नहीं, बल्कि हत्या का आरोपी एक दूसरा छात्र है। यही कारण है कि निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के मामलों में केवल सीबीआइ जांच की मांग की जाती है। अलग-अलग मामलों की जांच का बहुत अधिक बोझ इस विभाग पर है। दूसरा पक्ष है कि सीबीआइ एक स्वायत्त विभाग है, लेकिन सत्ता पक्ष द्वारा जांच को प्रभावित करने के आरोप भी लगते रहे हैं। ऐसे में उच्च स्तर के अधिकारियों की स्वतंत्र नियुक्ति को लेकर सुधार करने की आवश्यकता है। विश्वस्तर की जांच एजेंसिया साधन संपन्न और तकनीकी लिहाज से काफी विकसित होती हैं, लेकिन भारतीय जांच एजेंसी साधनों के मामले में पीछे है। समय के साथ सीबीआइ की स्वायत्तता और शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। जिससे एफबीआइ, सीआइ के समतुल्य बनाया जा सकता है।

mkumar.sidhmukh@gmail.com

वोट की राजनीति

वोट के खातिर भारतीय नेता राजनीति में भी उदंड राजनीति करने लगते हैं और हर तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उस जाति या धर्म के अंदर उनकी पार्टी की साख बन जाए और वे वोट प्रतिशत को बनाए रखने में कामयाब रहे। इसी तरह की राजनीति करने में विपक्षी दल भी लगे हुए हैं, वह हर प्रकार से वोट प्रतिशत बढ़ाने में लगे हैं, चाहे वह भारत बंद के जरिए हो या फिर आरक्षण खत्म करने की अफवाह। दलितों को आकर्षित करने के लिए एक दिन का सांकेतिक उपवास रखने की योजना के तहत कांग्रेस पार्टी खुद उपहास का पात्र बन गई, दिखाने के लिए कि हम उपवास कर रहे हैं और उपवास से पहले ही कई कांग्रेसी नेता छोले-भटूरे खाकर कर तृप्त हो गए, उसके बाद महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर बैठ गए। अब इन नेताओं के छोले-भटूरे खाकर उपवास का नाटक करने की क्या मंशा थी? यह तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि ये नेता वोट की राजनीति जरूर कर रहे हैं। आज देश को पता चल गया कि ये नेतागण दलितों के कितने हितैषी हैं। अगर देखा जाए तो दलित वर्ग का हितैषी कोई नहीं है, लेकिन आम जनता भी इन नेताओं के छलावे में आकर फंस जाती है।

pathaknirajkumar2013@gmail.com

बनाए रखें आपसी प्रेम

आजादी के कई साल बाद भी हम संकुचित मानसिकता से आजाद नहीं हुए हैं। पहले विदेशी हमें आपस में लड़ा कर देश को लूटते रहे और आज हम खुद आपसी मतभेद व जाति-पात के चक्कर में देश तथा समाज को बांट रहे हैं। गरीब और मजदूर वर्ग को इन बातों से कोई सरोकार नहीं होता कि भारत बंद क्या होता है? भारत आजाद देश है और इसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता, यह हमें समझना होगा। सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी आंदोलन को देश के नाम से जोड़कर चलना क्या उचित है? देश में हिंसात्मक कार्य को बस कुछ ओछी राजनीति करने वाले लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ नेता ऐसे विवादों पर अपने राजनैतिक दांवपेंच अपना कर सिर्फ अपना फायदा देखते हैं उनको किसी भी जाति वर्ग, समाज, धर्म या अपने देश की कोई परवाह नहीं होती। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां सभी धर्म और जातियों का बराबर सम्मान होता है और यह हम सब का अधिकार भी है। आम आदमी ही नहीं यदि कोई भी नेता या कोई खास व्यक्ति भी जाति, धर्म या देश को अपमानित करने व अनुचित बात करता है या ऐसी किसी भी बात का समर्थन करता है, तो तुरंत उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश में शांति, समानता और भाईचारे के साथ रहने का हम सभी को अधिकार प्राप्त हैं और इनको कोई नहीं छीन सकता बस हमें इनको समझने और अपनाने की जरूरत है। हम सभी को समाज और देश में आपसी प्रेम और भाईचारे को बना कर रखने की जरूरत है।

ramdevtanwar@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

चांदनी चौक के चैना राम तो भटूरे खिलाकर चैन से सो गए होंगे, लेकिन उनके भटूरों ने कांग्रेसियों का चैन छीन लिया।
समीर अब्बास@TheSamirAbbas

योगी शासन को अराजक करार देकर सपा-बसपा के गुंडाराज से तुलना करना बकवास है। 25 करोड़ की आबादी वाले सूबे को संभालना आसान नहीं। योगी द्वारा शासन में बदलाव की तमाम कोशिशों के बावजूद जरा सा मौका मिलते ही उन्हें पद से हटाने के लिए आवाजें बुलंद होने लगती हैं।
विकास सारस्वत@VikasSaraswat

दिल्ली हवाई अड्डा जेएफके एयरपोर्ट को पछाड़कर दुनिया के 20 व्यस्ततम हवाई अड्डों में शुमार हो गया। यह एक बड़ा आकार लेती अर्थव्यवस्था का संकेत है। बुनियादी ढांचे की पिछली तेजी गायब हो गई थी, मगर यह